



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

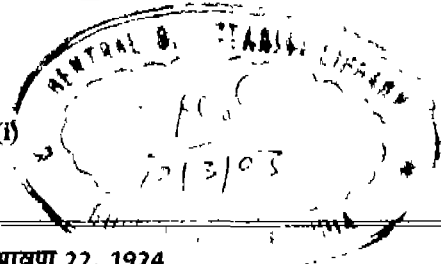
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 369]

No. 369]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2002/श्रावण 22, 1924

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2002/SRAVANA 22, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 38/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 560(अ)— केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल)

अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 52/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19 अक्टूबर, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में, “माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए” शब्दों के स्थान पर “यूनिट स्थापित करने के प्रयोजन के लिए या माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 314/24/2001-एफटीटी(पीटी)]

डी. एस. गरब्याल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 52/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19 अक्टूबर, 2000, सा. का. नि. 803(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 36/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 25 जून, 2002, सा. का. नि. 448 (अ), तारीख 25 जून, 2002 द्वारा किये गये थे।

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2002

No. 38/2002-Central Excise

G.S.R. 560(E):— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1994 (1 of 1994), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) vide No.52/2000-Central Excise, dated the 19th October, 2000, namely,-

In of the said notification, in the opening paragraph, for the words “for the purposes of manufacture of goods”, the words “for the purposes of setting up of units or for the purposes of manufacture of goods” shall be substituted.

[F No. 314/24/2001-FTT(Pt)]

D S GARBYAL, Under Secy

Note: The principal notification No. 52/2000-Central Excise, dated the 19th October, 2000, was issued vide GSR 803(E), dated the 19th October, 2000, and was last amended by notification No. 36/2002-Central Excise, dated the 25th June, 2002, issued vide GSR 448(E) dated the 25th June, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 39/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 561(अ)— केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल)

अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क्य माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को, विशेष आर्थिक जोन में, विशेष आर्थिक जोन के किसी विकासकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और अनुसूक्षण के प्रयोजन के लिए, भारत के अन्य भागों में स्थित विनिर्माण कारखाने या भांडागार से लाया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

- (i) विकास आयुक्त द्वारा विकासकर्ता को विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और अनुक्षण करने की अनुज्ञा दी गई है ;
- (ii) उक्त माल को, विनिर्माण कारखाने या भांडागार से लाए जाने के लिए उक्त विशेष आर्थिक जोन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;
- (iii) उक्त माल, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 57 या धारा 58 के अधीन, यथास्थिति, लोक भांडागार या निजी भांडागार के रूप में नियुक्त या अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों में भंडारित किए जाएंगे ;
- (iv) आयातकर्ता, उक्त माल के आयात या उपापन, उपभोग और उपयोग का समुचित लेखा रखेगा और उक्त विशेष आर्थिक जोन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को ऐसे प्रारूप में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा ;
- (v) उक्त माल को विशेष आर्थिक जोन से हटाने की तब के सिवाय अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त विशेष आर्थिक जोन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा अनुज्ञा न दे दी गई हो और लागू शुल्क का संदाय न कर दिया गया हो ; और
- (vi) आयातकर्ता, छह मास की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, उक्त माल का उपयोग करने के लिए स्वयं को आबद्ध करते हुए, एक बंधपत्र, ऐसे प्रारूप और ऐसी रकम के लिए, जो यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विहित की जाए, निष्पादित करेगा और यदि विकासकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो वह मांग किए जाने पर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क और उक्त शुल्क पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित बराबर रकम का, उक्त माल के आयात करने या उपापन की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय होने तक संदाय करेगा ।

[फा. सं. 305/24/2001-एफटीटी(पीटी)]

डी. एस. गरब्याल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2002

No. 39/2002-Central Excise

G.S.R. 561(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods specified in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the said goods), when brought into a special economic zone by a developer of special economic zone from factory of manufacture or warehouse situated in other parts of India, for the purposes of development, operation and maintenance of special economic zone, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Central Excise Act, and the additional duty of excise leviable thereon under subsection (1) of section 3 of the said Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, subject to the following conditions, namely:-

- (i) the developer has been granted permission by the Development Commissioner to develop, operate and maintain the special economic zone;
- (ii) the said goods have been authorised to be brought from the factory of manufacture or warehouse by a Committee headed by the Chief Commissioner of Customs or the Chief Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over said special economic zone;
- (iii) the said goods shall be stored in the premises appointed or licensed as public warehouse or private warehouse, as the case may be, under section 57 or section 58 of the Customs Act, 1962 (1 of 1962);
- (iv) the developer shall maintain proper account of procurement, consumption and utilisation of the said goods and submit quarterly statement to the Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the said special economic zone in such Form as may be specified by him;

- (v) the said goods shall not be allowed to be removed from the special economic zone except with the permission of the Assistant or Deputy Commissioner of Customs or the Assistant or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the said special economic zone, and on payment of applicable duty; and
- (vi) the developer shall execute a bond in such Form and for such sum as may be specified by the Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, binding himself to utilise the said goods within a period of six months or such extended period as may be allowed by him, and if the developer fails to do so, then he shall pay, on demand, an amount equal to the duty as leviable on the said goods along with interest at the rate of 15 per cent. per annum on the said duty from the date of procurement of the said goods till the payment of such duty.

[F No 305/24/2001-FTT(Pt)]

D S GARBYAL, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 81/2002-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 562(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 137/2000-सीमाशुल्क, तारीख 19 अक्टूबर, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के आरंभिक पैरा में, “माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए” शब्दों के स्थान पर “यूनिट स्थापित करने के प्रयोजन के लिए या माल के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 314/24/2001-एफटीटी(पीटी)]

डी. एस. गरब्याल, अपर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना सं. 137/2000-सीमा शुल्क, तारीख 19 अक्टूबर, 2000, सा. का. नि. 804(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2000 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 65/2002-सीमा शुल्क, तारीख 25 जून, 2002, सा. का. नि. 449(अ), तारीख 25 जून, 2002 द्वारा किये गये थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2002

No. 81/2002-Customs

G.S.R. 562(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) vide No.137/2000-Customs, dated the 19th October, 2000, namely,-

In the said notification, in the opening paragraph, for the words “ for the purposes of manufacture of goods”, the word “ for the purposes of setting up of units or for the purposes of manufacture of goods ” shall be substituted.

[F. No 314/24/2001-FTT(Pt.)]

D S GARBYAL, Under Secy

Note: The principal notification No. 137/2000-Cus, dated the 19th October, 2000, was issued vide GSR 804(E), dated the 19th October, 2000, and was last amended by notification No. 65/2002-Customs, dated the 25th June, 2002, issued vide GSR. 449 (E) dated the 25th June, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2002

सं. 82/2002-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 563(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) जब उसका विशेष आर्थिक जोन के किसी विकासकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयातकर्ता कहा गया है) द्वारा विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और अनुक्षण के प्रयोजन के लिए भारत में आयात किया जाए या यथास्थिति, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 57 या धारा 58 के अधीन नियुक्त या अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी लोक भांडागार या किसी निजी भांडागार से उपाप्त किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से, यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

- (i) विकास आयुक्त द्वारा विकासकर्ता को विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और अनुक्षण करने की अनुज्ञा दी गई है ;
- (ii) उक्त माल को विनिर्माण कारखाने या भांडागार से आयातित किए जाने या उपाप्त किए जाने के लिए, उक्त विशेष आर्थिक जोन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;
- (iii) उक्त माल, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 57 या धारा 58 के अधीन, यथास्थिति, लोक भांडागार या निजी भांडागार के रूप में नियुक्त या अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों में भंडारित किए जाएंगे ;

- (iv) विकासकर्ता, उक्त माल के उपापन, उपभोग या उपयोग का समुचित लेखा रखेगा और उक्त विशेष आर्थिक जोन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को ऐसे प्ररूप में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा ;
- (v) उक्त माल को विशेष आर्थिक जोन से हटाने की तब के सिवाय अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उक्त विशेष आर्थिक जोन पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त द्वारा अनुज्ञा न दे दी गई हो और लागू शुल्क का संदाय न कर दिया गया हो ; और
- (vi) विकासकर्ता, छह मास की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, उक्त माल का उपयोग करने के लिए स्वयं को आबद्ध करते हुए, एक बंधपत्र, ऐसे प्ररूप और ऐसी रकम के लिए, जो यथास्थिति, सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विहित की जाए, निष्पादित करेगा और यदि विकासकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो वह मांग किए जाने पर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क और उक्त शुल्क पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित बराबर रकम का, उक्त माल का उपापन करने की तारीख से, ऐसे शुल्क के संदाय होने तक, संदाय करेगा ।

[फा. सं. 305/24/2001-एफटीटी(पीटी)]

डी. एस. गरब्याल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2002

No. 82/2002-Customs

G.S.R. 563(E):— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods (hereinafter referred to as the said goods), when imported into India or procured from a Public Warehouse or a Private Warehouse appointed or licensed, as the case may be, under section 57 or section 58 of the said Customs Act by a developer (hereinafter referred to as the importer) of special economic zone for the purpose of development, operation and maintenance of special economic zone, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty, if any, leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely:—

- (i) the importer has been granted permission by the Development Commissioner to develop, operate and maintain the special economic zone;
- (ii) the said goods have been authorised to be imported or procured from a Public Warehouse or a Private Warehouse by a Committee headed by the Chief

- Commissioner of Customs or the Chief Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the said special economic zone;
- (iii) the said goods shall be stored in the premises appointed or licenced as Public Warehouse or Private Warehouse, as the case may be, under section 57 or section 58 of the said Customs Act;
- (iv) the importer shall maintain proper account of import or procurement, consumption and utilisation of the said goods and shall submit a quarterly statement to the Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the said special economic zone, in such Form as may be specified by him;
- (v) the said goods shall not be allowed to be removed from the special economic zone except with the permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the said special economic zone, and on payment of applicable duty; and
- (vi) the importer shall execute a bond in such Form and for such sum as may be specified by the Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, binding himself to utilise the said goods within a period of six months or such extended period as may be allowed by him, and if the importer fails to do so, then he shall pay, on demand, an amount equal to the duty as leviable on the said goods alongwith interest at the rate of 15 per cent. per annum on the said duty from the date of importation or procurement of the said goods till the payment of such duty.

[F. No. 305/24/2001-FTT(Pt)]

D. S. GARBYAL, Under Secy.